कमी के कारण देश के अन्य जगहों से अच्छे उद्योगपति इस पूर्वांचल में उद्योग लगाने के लिए उत्सुक नहीं रहते हैं।

मुझे ज्ञात हुआ है कि गत कुछ दिन पहले सरकार इस हवाई अड्डे के विस्तार हेतु कुछ कदम उठाने वाली थी किन्तु अभी तक उसमें कुछ प्रगति नहीं दिखाई दे रही है। अत: केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि आर्थिक, व्यापारिक, औद्योगिक, सैनिक एवं वैज्ञानिक मूल्यों को मजबूत बनाने हेतु उक्त हवाई अड्डे के विस्तार को ठीक करने के लिए विशेष धनराशि स्वीकृत करके अविलम्ब कार्यवाही करें। मान्यवर, ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर सप्ताह में केवल तीन ही दिन यात्री विमान रुकने की व्यवस्था है। अत: सम्बन्धित माननीय मंत्री से विनम्र निवेदन है कि उक्त स्थान पर प्रत्येक दिन वायुयान रुकने के लिए अविलंब आदेश प्रदान करें ताकि उक्त स्थान को आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ा सकें। ऐसा करने से भारतीय पर्यटन विभाग को काफी प्रोत्साहन मिलेगा और विश्व के अन्य देशों से आने वाले यात्रियों से मुद्रा कमा सकेंगे।

(v) NEED FOR SETTING UP OF A BENCH OF ALLAHABAD HIGH COURT AT MEERUT.

SHRI GEORGE FERNANDES (Muzaffarpur) : There has been a long standing demand from the District Bar Associations and from the pople of the districts of Western Uttar Pradesh a for the setting up of a Bench of the Allahabad High Court in Meerut. The demand was backed by frequent agitation involving large sections of the people of the region. The Banarsi Das Ministry had made a recommendation to the Central Government to set up such a Bench. Unfortunately, there has been no positive action by the Central Government on this demand.

In the meanwhile, there has been a major escalation in the agitation for setting up of the Bench. During the last two months, the lawyers have been intermittently boycotting the courts and this has created a sitauation where several thousand undertrials are languishing in prisons all through Western Uttar Pradesh without their trial being proceeded with and/ or without getting bail.

The District Bar Associations, trade unions and mass organisations, farmers' organisations and political parties have now given a call for *bandh* in the districts of Western Uttar Pradesh on March 16. This will result in dislocation of normal life in the region. Worse, this will trigger off a mass movement which may create, among other things, a law and order situation in the entire region.

Uttar Pradesh is a large State of long distances and a population that is one seventh of the population of the country. The State High Court located in Allahabad has one other Bench located in Lucknow. Justice in Uttar Pradesh is, therefore, both delayed and expensive. The demand of the people for a Bench in Western Uttar Pradesh is fully justified. It will save the litigants from these districts a lot of money, time and harassment. I would urge the Law Minister not to delay taking a decision on this matter any further, and to give assent to the unanimous recommendation of the Lok Dal Ministry headed by Banarsi Das to set up a Bench in Meerut. (*Interruptions*)

(vi) NON-EMPLEMENTATION OF PALEKAR AWARD BY THE MANAGEMENT OF A U. P. HINDI DAILY '*Bharat*'.

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : पालेकर एवार्ड को अधिकांश समाचारपत्र मालिकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा ऐसे समाचारपत्र मालिकों की भी कमी नहीं है जिन्होंने इसे लागू ही नहीं किया—और उसी से बचने के लिए अदालत चले गए हैं अथवा यदि लागू भी किया है तो तोड़-मरोड़ कर अपनी सुविधानुसार किया है। कुछ मालिकों ने अपने यहां छंटनी कर दी है और कुछ समाचारपत्र मालिकों ने तो इस पालेकरएवार्ड से बचने के लिए समाचारपत्रों का प्रकाशन

[श्री आर० एन० राकेश]

ही बन्द कर दिया है। दैनिक "भारत" इनमें से एक है। उल्लेखनीय है कि "भारत" के मालिक देश के सब से बड़े उद्योगपति बिड़ला हैं।

देश की स्वतन्त्रता से 15 वर्ष पूर्व 1932 में "भारत" का प्रथम अंक निकला था। महामना पंडित मदनमोहन मालवीय, पं० मोतीलाल नेहरू, डा० तेज बहादुर सप्रू, डा० सच्चिदानन्द सिन्हा तथा राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन के आग्रह प्रेरणा और आशिर्वचन लेकर "भारत" ने देश के जन-जीवन से जुड़ने के लिए अपनी यात्रा आरम्भ की थी। आजादी के बाद इस "भारत" ने प्रयाग, उत्तर प्रदेश और देश के लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं को निरन्तर अभिव्यक्त कर के अपने दायित्व को सदैव सजग लक्ष्य की भांति अनेक झंझावातों के कठोर थपेड़े को सहते हुए भी आज तक पूरा किया है।

इसी संस्था ने इलाहाबाद से ही प्रकाशित होने वाले "लीडर" को भी बन्द कर दिया है। हकीकतन यदि यह सच है कि देश की आजादी की लड़ाई में इलाहाबाद की विशेष अहमियत है तो यह भी सच है कि इसमें "भारत" और "लीडर" दोनों समाचारपत्रों की भूमिका अति गौरवमयी है। उक्त प्रेस की पचासों लाख की मौजूदा सम्पत्ति इन्हीं "भारत" और "लीडर" की गाढ़ी कमाई है। पालेकर एवार्ड से बचने के लिए "भारत" के प्रकाशन को ही प्रकाशक तथा मालिकों द्वारा बन्द कर दिया गया है जिससे दैनिक "भारत" समाचारपत्र सम्बन्धित पत्रकारगण और मजदूरों के जीवकोपार्जन के लाले पड़े गए हैं। ऐसा लगता है कि समाचारपत्र को बन्द करके इसके मालिकगण "भारत" की उक्त सम्पत्ति को किसी अन्य कार्य में लेना चाहते हैं जोकि घोर आपत्तिजनक है। मैं चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई में "भारत" की भूमिका के सम्मान, उत्तर भारत के आठ लाख पाठकों की आकांक्षा और पत्रकारों के हितों की रक्षा हेतु सरकार अविलम्ब हस्तक्षेप करे और प्रकाशकों के नापाक इरादों को पूरा न होने दे।

(vii) REPORTED SUGGESTION BY WORLD BANK TEAM FOR IMPORT OF HIGH POWERS LOCOMOTIVES BY INDIA.

PROF MADHU DANDAVATE: (Rajapur) It is reported that the World Bank team which recently visited India, had eleborate discussions with the Railway experts and the team indicated that no World Bank aid would be available to the Indian Railways, unless the Railways decide to have computerised management system so as to adequately plan the rolling stock, wagon loading review all India marshalling orders and organise up-dated reservation system.

The World Bank has suggested the import of high power locomotives.

AN HON. MEMBER : High powered locomotives ? You were the Railways Minister.

PROF. MADHU DANDAVATE: Please do not be disturbed. I am not referring to you. I am referring to the World Bank. I have never imported high powe locomotives.

In the past also there have been pressures for the import of high power locomotives. But the railways resisted these pressures, in view of the fact that the railways were self-sufficient in locomotives and there was no need of import of high power locomotives; instead, an exper ment of double headed trains was attempted.

The Railway Minister should make a categorical statement whether the Railway administration desires to reverse its past attitude towards the import of high power locomotives.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : (Diamond Harbour) Sir on a point of order.